International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Impact Factor: 6.340, Volume 04, No. 01(III), January - March, 2022, pp.31-34

बजट 2022–23 के विभिन्न आयामों का अध्ययन

श्री गौरव साहू*
डॉ. श्रीमती महेन्द्र मेहता**

सार

रीन स्टोर्म के अनुसार ''बजट एक लेख पत्र है, जिसमें सरकारी आय और व्यय की एक प्रारंभिक अनुमोदित योजना रहती है।'' हर वर्ष सरकार अपने देशवासियों के सामने अपने आने वाले वर्ष के लिये बजट प्रस्तुत करती है। सर्वप्रथम देश का बजट वर्ष 1860, 07 अप्रैल को पेश किया गया था। 01 फरवरी 2022 को केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लोकसभा में बजट पेश किया गया व भारत की अर्थव्यवस्था के लिये सरकार द्वारा बनायी गयी अनेक योजनाओं को साझा किया। अमृतकाल का यह बजट देश के युवाओं, महिलाओं, कृषकों व अनुसूचित जनजाति वर्ग को प्रत्यक्षतः लाभ पहुंचायेगा। सरकार द्वारा देश के समावेशी विकास हेतु अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में किये गये विनियोग से अर्थव्यवस्था को और भी अधिक मजबूती मिलेगी तथा हमारा देश सुदृढ़ होगा।

शब्दकोश: *बजट, समावेशी, अमृतकाल।*

प्रस्तावना

गत वर्ष व चालू वर्ष की विभिन्न वित्तीय गतिविधियों तथा सरकार की प्रस्तावित भिन्न–भिन्न आर्थिक नीतियों का विस्तृत वर्णन और साथ ही साथ आगामी वर्ष हेतु सरकार के अनुमानित आंकड़ों का ब्यौरा ही बजट कहलाता है। बजट हम सभी के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका का वहन करता है। जिस प्रकार हम स्वयं के घरेलू खर्चे व निवेशों का फैसला अपना बजट बनाकर ही करते हैं, उसी प्रकार सरकार भविष्य में होने वाले आय–व्यय का लेखा–जोखा बजट बनाकर ही संपन्न करती है। हर वर्ष सरकार अपने देशवासियों के सामने आने वाले वर्ष के लिये बजट प्रस्तुत करती है। बजट का उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष के हित में न होकर देश के आर्थिक हित में होना चाहिये। भारत देश के बजट का इतिहास 162 वर्ष पुराना है। सर्वप्रथम देश की बजट वर्ष 1860, 7 अप्रैल को पेश किया गया था। आजादी के पश्चात् भारत का पहला बजट 26 नवंबर, 1947 को पेश किया गया था। वर्ष 2017 तक देश का रेल व आम बजट अलग–अलग पेश किया जाता था। परन्तु वर्ष 2017 के पश्चात् दोनों का विलय कर दिया गया। वर्तमान में केवल एक ही बजट पेश किया जाता है। 01 फरवरी, 2022 को केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा लोकसभा में बजट पेश किया गया तथा आने वाले वित्तीय वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था के लिये सरकार द्वारा बनायी गयी अनेक योजनाओं को साझा किया गया हैं।

उद्देश्य

बजट 2022 का उद्देश्य अमृतकाल में निम्न लक्ष्यों को पूरा करना है –

- व्यापक आर्थिक विकास में सहायता हेतु सूक्ष्म आर्थिक स्तर व समग्र कल्याण पर ध्यान देना।
- डिजीटल अर्थव्यवस्था व फिटनेक, प्रौद्योगिकी समर्पित विकास, ऊर्जा परिवर्तन व जलवायु कार्य योजना को बढ़ावा देना।
- सार्वजनिक पूंजी निवेश की सहायता के बिना निजी निवेश से सहायता उपलब्ध कराना।

---

* सहायक प्राध्यापक, वाणिज्य एवं वित्तीय अध्ययन विभाग, अटल बिहारी वाजपेयी विण्वि, बिलासपुर (छ.ग.)।
** सहायक प्राध्यापक, वाणिज्य एवं वित्तीय अध्ययन विभाग, अटल बिहारी वाजपेयी विण्वि, बिलासपुर (छ.ग.)।

शोध प्रविधि

शोध विषय हेतु यथासंभव प्रभूत सामग्री का संकलन करके उसका सूक्ष्मतर विश्लेषण व विवेचन तथा नए सिद्धांतो के प्रतिपादन की प्रक्रिया ही शोध प्रविधि कहलाती है। प्रस्तुत शोध पत्र हेतु द्वितीयक समंकों का संग्रहण किया गया है, जिसे विभिन्न पत्र–पत्रिकाएं, सरकारी प्रकाशन, वित्तीय आयोगों की रिपोर्ट, अनुसंधान संस्थाओं के प्रकाशन व इंटरनेट के विभिन्न वेबसाईट से लिया गया है।

प्राथमिकताओं का निर्धारण

अमृतकाल के इस बजट से देश के युवाओं, महिलाओं, किसानों व अनुसूचित जनजाति को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचेगा। आधुनिक अधोसंरचना जो 100 वर्षों के लिये होगी, के लिये सार्वजनिक निवेश जैसी व्यवस्थाएं की गयी है। सरकार द्वारा चार प्राथमिकताओं का निर्धारण किया गया है :–

- पी एम गतिशक्ति
- समावेशी विकास
- निवेशों का वित्तपोषण
- उत्पादकता में वृद्धि एवं विनियोग, ऊर्जा में होने वाले परिवर्तन व जलवायु कार्य योजना।

समावेशी विकास

सरकार द्वारा देश के समावेशी विकास हेतु अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में किये गये विनियोग व योजनाओं को बजट में समावेश किया गया, जिसमें प्रमुख क्षेत्र हैं –

कृषि

- एम एस पी मूल्य का 2.37 करोड़ रूपये का भुगतान सीधे कृषकों के खातों में किया जायेगा।
- रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जायेगा।
- कृषकों को डिजीटल और हाइटेक सेवाएं देने हेतु पीपीपी मॉडल में योजना शुरू की जावेगी।
- पोषक तत्वों हेतु ''किसान ड्रोन '' के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा।
- कृषि विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में संशोधन हेतु राज्यों को प्रोत्साहित किया जावेगा तथा आग्रेनिक व प्राकृतिक फार्मिंग की ओर ध्यान दिया जावेगा।

एमएसएमई

- ई–श्रम, उद्यम और इस तरह के अनेक पोर्टल्स को आपस में जोड़ा जावेगा और ये पोर्टल्स लाइव आग्रेनिक डेटा बेस होंगे।
- कौशल विकास पर ध्यान दिया जावेगा।
- कोरोना महामारी के प्रतिकूल प्रभाव से राहत के लिये ईसीएलजीएस के तहत् 130 लाख से भी अधिक एमएसएमई को अत्यंत ही आवश्यक और अतिरिक्त कारण प्रदान किया जायेगा।

नेशनल टेलमेंटल हेल्थ प्रोग्राम

कोरोना महामारी ने सभी आयु वर्गों में मानसिक स्वास्थ्य की समस्या को बढ़ा दिया है। इस हेतु ''नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम'' प्रारंभ किया जायेगा।

हर घर, नल से जल

इसके अंतर्गत 8.7 करोड़ परिवारों को शामिल किया गया है। इस हेतु वर्ष 2022–23 में 3.8 करोड़ परिवारों को 60,000 करोड़ रूपये का आबंटन किया गया है।

किसी भी समय कहीं भी डाकघरों में बचत :–

1.5 लाख डाकघरों में वर्ष 2022 में फोर बैंकिंग सिस्टम चालू हो जायेगा, जिससे वित्तीय समावेशन संभव होगा और अपना खाता नेटबैंकिंग के माध्यम से देखा जा सकेगा। एटीएम की भी सुविधा होगी साथ ही साथ डाकघर के खाते से बैंक के खाते के बीच ऑनलाईन पैसे का अंतरण भी हो पाएगा।

कौशल विकास

रोजगार की क्षमता को बढ़ाने के लिये व रोजगार में स्थायित्व हेतु कौशल विकास कार्यक्रमों और उद्योगों के साथ उनकी भागीदारी को एक नयी दिशा दी जा सकेगी।

डिजीटल विश्वविद्यालय

देश के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो सके, इस हेतु डिजीटल विश्वविद्यालय की स्थापना की बात बजट में की गयी है।

महत्वकांक्षी ब्लाक कार्यक्रम

देश के नागरिक जो अत्यंत दुर्गम और पिछड़े जिलों में निवास करते हैं, उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार हेतु यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस प्रकार के 112 जिलों के 95 प्रतिशत क्षेत्रों में पोषण, स्वास्थ्य, वित्तीय स्थिति और अवसंरचना में काफी प्रगति हुयी है। लेकिन कुछ जिलाखण्ड अभी भी पिछड़े हुये हैं। अतः वर्ष 2022–23 में महत्वकांक्षी ब्लाक्स कार्यक्रम के अंतर्गत इस प्रकार के पिछड़े जिलों के ब्लाक्स पर ध्यान दिया जावेगा।

ई–पासपोर्ट

ई–पासपोर्ट जारी करने के लिये वर्ष 2022–23 में इम्बेडेड चिप और प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जायेगा जिससे भारत के नागरिक विदेश की यात्रा और सुविधापूर्वक कर सकेंगे।

पीएम–डीईएआईएनई

''प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनीशिएटिव फॉर नार्थ ईस्ट रीजन'' नाम की एक नयी योजना उत्तर–पूर्व परिषद् के माध्यम से चलायी जावेगी। इससे उत्तर पूर्व की आवश्यकताओं के अनुरूप ही बुनियादी सुविधाओं और सामाजिक विकास हेतु परियोजनाओं के लिये वित्त उपलब्ध करवाया जा सकेगा। इस हेतु केन्द्र सरकार द्वारा 1500 करोड़ रूपये का प्रारंभिक रूप से आबंटन किया गया है जिसकी सूची निम्न प्रकार से है :–

पीएम डिवाइन के तहत् परियोजनाओं की आरंभिक सूची

क्र. स.	परियोजना का नाम	कुल अनुमानित लागत (करोड़ रूपए में)
1.	पूर्वोत्तर भारत गुवाहाटी (बहु–राज्य) में बाल रोग और व्यस्क हीमोटोलिम्फोइड कैंसरों के प्रबंधन हेतु समर्पित सेवाओं की स्थापना	129
2.	नेकटेयर आजीविका संवर्धन परियोजना (बहु–राज्य)	67
3.	पूर्वोत्तर भारत (बहु–राज्य) में वैज्ञानिक ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा	45
4.	पश्चिम की ओर आईजोल बाईपास का निर्माण	500
5.	सिक्किम पश्चिम में संगा–चौलिंग के लिए पैलिंग हेतु यात्री रोपवे सिस्टम हेतु अंतर – निधियन	64
6.	दक्षिण सिक्किम में धैप्पर से भाले धुंगा तक वातावरण अनुकूल रोपवे (केबल कार) के लिए अंतर–निधियन	58
7.	मिजोरम राज्य में विभिन्न जिलों में भिन्न–भिन्न स्थानों पर बांस संपर्क सड़क के निर्माण के लिए प्रायोगिक परियोजना	100
8.	अन्य (चिन्हित की जानी है)	537
	कुल	**1500**

स्त्रोतः budget 2022-23 hindi pdf

अन्य योजनाएं

बजट वर्ष 2022–23 में सरकार ने अन्य अनेक योजनाओं को क्रियान्वित करने की घोषणा की है। सभी के लिये आवास, मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, महत्वकांक्षी ब्लॉक्स कार्यक्रम, डिजीटल बैंकिंग, डिजीटल पेमेंट्स, ई– पासपोर्ट, बैट्री अदला–बदला नीति जैसे अनेक योजनाएं सरकार द्वारा घोषित की गयी।

समीक्षा

- बजट 2022 के उद्देश्यों में समग्र कल्याण पर ध्यान देना जैसी बातें वर्णित है परन्तु मनरेगा कानून में लगातार दूसरे वर्ष में भी बजट प्रावधान में कटौती की गयी, जिसका सीधा मतलब रोजगार में कमी से है।
- केन्द्र सरकार का कृषि क्षेत्र के लिये ड्रोन के उपयोग पर जोर दिया जायेगा।
- जो कृषक एग्रो–फॉरेस्ट्री को लेकर कार्य करना चाहते हैं, उन्हें वित्तीय सहायता दी जायेगी।
- देश के मध्यम वर्गीयों को इस बजट से महंगाई, बेरोजगारी व टैक्स से छूट को लेकर बड़ी उम्मीदें थी, पर ऐसी घोषणा नहीं हुयी साथ ही साथ वर्चुअल करेंसी पर 30 प्रतिशत टैक्स की घोषणा की गयी है। कोरोनाकाल में देश बहुत ही बुरे दौर से गुजरा है, जिसका प्रभाव कृषि क्षेत्र पर भी पड़ा है। चूंकि सबसे ज्यादा रोजगार निर्माण कृषि क्षेत्र में हो सकता है इस हेतु सरकार को इस क्षेत्र में विनियोग करने की आवश्यकता है।
- कृषि क्षेत्र में नवाचार व नई तकनीक की आवश्यकता है।
- सरकार नाबार्ड की सहायता से ग्रामीण क्षेत्रों में स्टार्टअप करा सकती है।
- सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में अधोसंरचना हेतु 500 करोड़ कृषि कोष की घोषणा की गयी है, जोकि संतोषजनक नहीं है।
- सरकार को कौशल विकास मंत्रालय की स्थापना की ओर भी ध्यान देना चाहिये। सरकार के द्वारा कृषि अनुसंधान गांवों तक कैसे पहुंचे, इसकी भी पहल की जानी चाहिये।
- कृषि उन्नति योजना में सरकार द्वारा 7183 करोड़ रूपये विनियोग किये जाने की पहल सराहनीय है, इस योजना के तहत् डिजीटल कृषि पर ध्यान केन्द्रीत किया गया है।
- स्मार्ट सीटी की तरह ही स्मार्ट ग्रामों की बात भी की जानी चाहिये।
- बजट में गंगा के तटों पर खेती का प्रावधान प्रशंसनीय है।
- गति शक्ति योजना एक अनोखी योजना है। सभी विभागों के आपसी सामंजस्य से ही ये योजना सफल सिद्ध हो सकती है।
- दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिये पीपीपी मोड के अनुसार राष्ट्रीय रोपवे कार्यक्रम चलाये जाने की बात बजट में की गयी है। इसके तहत् वर्ष 2022–23 में आठ परियोजनाओं के लिये ठेके भी दिये जायेंगे। यह कदम सराहनीय है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. Studboosting.com/2021/or/budget-and-its-types-in-hindi.html
2. sarkariguider.com/bajat-kya-hai-in hindi
3. www.abplive.com
4. abplive.com/business/budget-2022
5. budget 2022-23 hindi pdf.pdf
6. www.downtoearth.org.in
7. www.ajtak.in>story>budget
8. www.drishtiias.com
9. www.livehindustan.com

❖◆❖